हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 12 अंक : 207 | देहरादून, बृहस्पतिवार, 08 फरवरी 2024 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 16

समानता, समरसता और सद्भाव कायम करेगा यूसीसी : स्वामी चिदानन्द 8

उत्तराखंड विधानसभा ने रचा इतिहास, सीएम धामी के नेतृत्व में पास हुआ यूसीसी बिल

समान नागरिक संहिता विधेयक पर दो दिनों तक हुई लंबी चर्चा

देहरादून। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक उत्तराखंड 2024 बुधवार को विधानसभा में पारित कर दिया गया। विधेयक पर दो दिनों तक लंबी चर्चा हुई। सत्ता और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों को लेकर अपने-अपने सुझाव दिए। इस प्रकार उत्तराखंड विधानसभा आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाली पहली विधानसभा बन गई है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 को विधानसभा में पेश किया था। आज बुधवार को सदन में विधेयक पर चर्चा के बाद सदन ने इसे पास कर दिया। अब अन्य सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। विधेयक में सभी धर्म-समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून का प्रावधान है। महिला-पुरुषों को समान अधिकारों की सिफारिश की गई है। अनुसूचित जनजातियों को इस कानून की परिधि से बाहर रखा गया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से किए गए वायदे के अनुसार पहली कैबिनेट बैठक में ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला किया।

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई। समिति ने व्यापक जन संवाद और हर पहलू का गहन अध्ययन करने के बाद यूसीसी के ड्रॉफ्ट को अंतिम रूप दिया है। इसके लिए प्रदेश भर में 43 जनसंवाद कार्यक्रम और 72 बैठकों के साथ ही प्रवासी उत्तराखंडियों से भी समिति ने संवाद किया।

कुप्रथाओं पर लगेगी रोक:

समान नागरिक संहिता विधेयक के कानून बनने पर समाज में बाल विवाह, बहु विवाह, तलाक जैसी सामाजिक कुरीतियों और कुप्रथाओं पर रोक लगेगी, लेकिन किसी भी धर्म की संस्कृति, मान्यता और रीति-रिवाज इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे। बाल और महिला अधिकारों की यह कानून सुरक्षा करेगा।

यूसीसी के अन्य जरूरी प्रावधान:

❖विवाह का पंजीकरण अनिवार्य। पंजीकरण नहीं होने पर सरकारी सुविधाओं से होना पड़ सकता है वंचित।

❖पति-पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित।

❖सभी धर्मों में विवाह की न्यूनतम उम्र लडक़ों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित।

❖वैवाहिक दंपत्ति में यदि कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे व्यक्ति की सहमति के अपना धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से तलाक लेने व गुजारा भत्ता लेने का पूरा अधिकार होगा।

❖पति-पत्नी के तलाक या घरेलू झगड़े के समय 5 वर्ष तक के बच्चे की कस्टडी उसकी माता के पास ही रहेगी।

❖सभी धर्मों में पति-पत्नी को तलाक लेने का समान अधिकार।

❖सभी धर्म-समुदायों में सभी वर्गों के लिए बेटा - बेटी को संपत्ति में समान अधिकार।

❖मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक।

❖संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज बच्चों में कोई भेद नहीं किया गया है। नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान माना गया है।

किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति में उसकी पत्नी व बच्चों को समान अधिकार दिया गया है। उसके माता-पिता का भी उसकी संपत्ति में समान अधिकार होगा। किसी महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे के संपत्ति में अधिकार को संरक्षित किया गया ।

❖लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य। पंजीकरण कराने वाले युगल की सूचना रजिस्ट्रार को उनके माता-पिता या अभिभावक को देनी होगी।

❖लिव-इन के दौरान पैदा हुए बच्चों को उस युगल का जायज बच्चा ही माना जाएगा और उस बच्चे को जैविक संतान के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे।

हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रऋषि नरेन्द्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उनके नेतृत्व में यह देश तीन तलाक और धारा-370 जैसी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के पथ पर है।

उत्तराखंड : 2010 के बाद हुई है शादी तो कराना होगा पंजीकरण, वरना लगेगा जुर्माना

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 08 फरवरी : अगर आपका विवाह 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, तो उसका पंजीकरण कराना होगा। पहले जो करा चुके हैं, उन्हें दोबारा पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। विधानसभा में पेश किए गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बिल में यह प्रावधान है। खास बात ये भी है कि कानून लागू होने के छह माह के भीतर पंजीकरण न कराने वालों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। पंजीकरण में गलत तथ्य देने वालों पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा।

यूसीसी में स्पष्ट किया गया कि विवाह करने वालों में से अगर स्त्री या पुरुष राज्य का निवासी होगा तो उसका पंजीकरण अनिवार्य होगा। 26 मार्च 2010 (उत्तराखंड अनिवार्य विवाह पंजीकरण एक्ट) तक के जो विवाह पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें यूसीसी लागू होने के बाद छह माह के भीतर पंजीकरण कराना होगा। जो पहले से पंजीकृत हैं, उन्हें कानून लागू होने के छह माह के भीतर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में घोषणा पेश करनी होगी। 2010 के पूर्व के दंपती चाहें तो अपना पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन उनकी एक से अधिक जीवनसाथी न हों। आयु का मानक पूरा हो रहा हो।

जानें कैसे होगा पंजीकरण

यूसीसी लागू होने के बाद पति-पत्नी मिलकर एक फार्म भरेंगे। विवाह की तिथि से 60 दिन के भीतर सब रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत करेंगे। शर्त है कि दोनों में से एक राज्य में निवास करता हो। इसी प्रकार, 2010 के पहले के दंपती के लिए भी औपचारिकताएं होंगी। यूसीसी के तहत राज्य सरकार सचिव स्तर के अधिकारी को रजिस्ट्रार जनरल (महानिबंधक) नियुक्त करेगी। इसके बाद उपजिलाधिकारी स्तर तक के अधिकारियों को रजिस्ट्रार और क्षेत्रों के लिए सब रजिस्ट्रार तैनात किए जाएंगे। यूसीसी में ये प्रावधान किया गया कि विवाह तभी होगा जबकि पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और स्त्री की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो।

10 से 25 हजार रुपये तक जुर्माना

कोई भी व्यक्ति जो विवाह होने के बाद जानबूझकर पंजीकरण नहीं

कराएगा या उपेक्षा करेगा, उस पर सब रजिस्ट्रार 10 हजार का जुर्माना लगा सकते हैं। जो व्यक्ति पंजीकरण में गलत तथ्य प्रस्तुत करेगा या कूटरचित दस्तावेज लगाएगा, उसे तीन माह की जेल और 25 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों लग सकते हैं। जो सब रजिस्ट्रार पंजीकरण प्रक्रिया, विच्छेद पर 15 दिन के भीतर एक्शन नहीं लेगा, उस पर भी 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

सब रजिस्ट्रार खुद भी ले सकते हैं संज्ञान

अगर कोई विवाह होता है और उसका पंजीकरण नहीं होता तो सब रजिस्ट्रार इसका खुद भी संज्ञान ले सकेगा। वह नोटिस भेजेगा, जिस पर 30 दिन के भीतर ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर 25 हजार का जुर्माना लगेगा। पंजीकरण न कराने पर कोई विवाह अविधिमान्य नहीं होगा।

नासा बनाएगा खास पॉवर प्लांट, चांद पर 10 साल लगातार मिलेगी बिजली

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 08 फरवरी : अगर आपको भी लगता है कि मंगल पर इंसानों का बसना मुमकिन नहीं है तो आपको यह खबर जरूर पढ़नी चाहिए. ऐसा इसलिए कि मंगल और चांद पर बस्ती बनाने क केवल ख्वाब ही नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसकी तैयारी तक हो रही है और अरबों का खर्चा भी हो रहा है. हाल ही में नासा ने पृथ्वी के बाहर न्यूक्लियर पॉवर प्लांट से बिजली बनाने की योजना का शुरुआती चरण पूरा किया है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मंगल और चंद्रमा के भावी अभियानों को ऊर्जा देने के लिए बहुत बड़ा कदम है। फिशन सर्फेस पॉवर प्रोजेक्ट नाम की इस परियोजना का मकसद एक छोटा सा न्यूक्लियर विखंडन रिएक्टर बनाना है जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ऊर्जा पैदा करेगा. यह लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए बहुत अहम है. नासा ने 2022 में अपने व्यवसायी साझेदारों को 50 लाख डॉलर के करार दिए थे, जिसमें हर एक को रिएक्टर की एक छोटे आकार की डिजाइन हो।

इससे चंद्रमा और मंगल पर भी लंबी उपस्थिति की दिशा में अहम उपलब्धि की तरह देखा जा रहा है. चंद्रमा पर तो इससे एक दशक तक इंसान रह सकेंगे. चंद्रमा पर खास तौर से सूर्य एक लगातार ऊर्जा देने वाला स्रोत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस पर 30 में से 15 दिन ही सूर्य की रोशनी रहती है. वहीं न्यूक्लियर पॉवर अगर नियंत्रित कर ली जाए तो सतत ऊर्जा दे सकती है। नासा ने कहा था कि रिएक्टर का वजन छह मेट्रिक टन से कम होना चाहिए और वह 40 किलोवाट की बिजली पैदा करने में सक्षम होना चाहिए जो एक दशक तक अपने आप काम कर सके. इसमें सुरक्षा को सबसे अधिक अहमियत दी गई थी. नासा का कहना है कि उसे उम्मीद से ज्यादा बेहतर समाधान मिले हैं। अब अगले चरण में नासा इन सुझावों को अमल में लाए जिसके बाद प्रक्षेपण में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इसी चरण में रिएक्टर की अंतिम डिजाइन का प्रदर्शन होगा. अंतिम चरण को नासा 2025 में शुरू करना चाहता है जिससे 2030 के दशक के शुरुआत में यह चंद्रमा पर भेजने के लिए तैयार हो जाए. रिएक्टर एक साल तक चंद्रमा पर प्रदर्शन के तौर पर काम करेगा जिसके बाद वह नौ साल तक काम करता रहेगा. सफल होने पर तनकीक को मंगल के लिए अपनाया जाएगा।

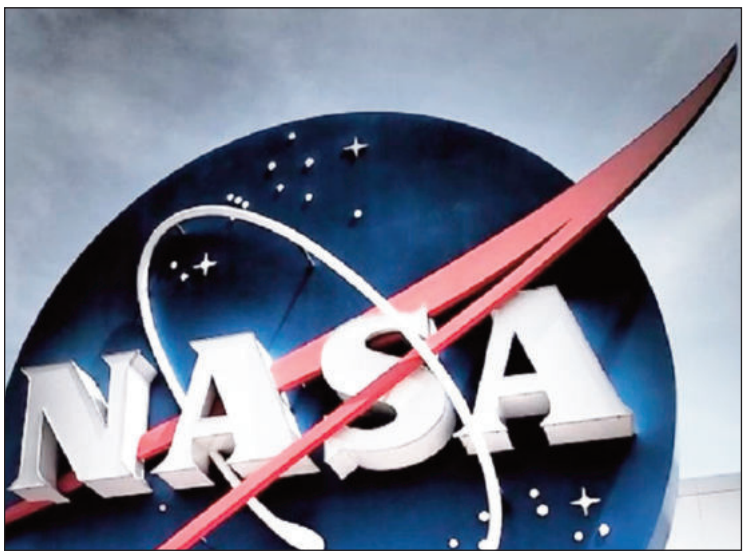

यहां पर मर्दों को करनी होती है दो शादी मना करने पर जाना पड़ता है जेल

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 08 फरवरी : दुनिया के हर देश में शादी के लिए अलग-अलग कानून हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर हर मर्द को दो शादी करना अनिवार्य है। अगर किसी पुरुष ने दो शादी करने से इंकार कर दिया, तो उसे अपना जीवन सलाखों के पीछे बिताना पड़ेगा। अफ्रीका महाद्वीप के देशों में शादी को लेकर अलग-अलग कानून हैं। लेकिन ऐसे कानून दुनिया के किसी और देश में नहीं हैं। अफ्रीका महाद्वीप के एक देश में अजीबो-गरीब कानून है। यहां पर मर्दों को दो शादी करनी अनिवार्य है। अगर किसी शख्स ने शादी करने से मना कर दिया, तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। आपको इस अनोखे देश के कानून के बारे में जानकर हैरानी हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी देश में ऐसा भी कानून हो सकता? आईए जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के इस देश के बारे में।

अफ्रीका महाद्वीप के इस देश में दो शादी करने के लिए अनोखा कानून बनाया गया है। इस अफ्रीकी देश का नाम इरीट्रिया है। यहां पर पुरुषों को दो शादी करना अनिवार्य है। अब पुरुष खुशी मन से शादी करे, या दुखी मन से। इरिट्रिया में दो शादी करना अनिवार्य है। अगर कोई पुरुष शादी करने या दो बीवियो को रखने से इंकार कर देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। अगर कोई दो शादी करने से इंकार करता है, तो उसे आजीवन जेल की सजा मिलती है। इस देश में महिलाओं की वजह से यह अनोखा कानून बनाया गया है। इरीट्रिया में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। इरीट्रिया का इथियोपिया से गृहयुद्ध चल रहा है जिसकी वजह से महिलाओं की संख्या यहां पर ज्यादा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस देश में महिलाओं के लिए भी कड़ा कानून है। यहां की महिलाएं पुरुषों को दो शादी करने से नहीं रोक सकती हैं। अगर उन्होंने शादी में कोई बाधा उत्पन्न की तो, उनको भी जेल में डाल दिया जाता है।

iPhone के लिए Camera Lens प्रोटेक्टर जरूरी या नहीं ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 फ़रवरी , जब भी बात iPhone की आती है तो 3 चीजों को लेकर हर कोई इसकी तारीफ करता दिख जाएगा। पहला इसका कैमरा, दूसरा सिक्योरिटी और तीसरा परफॉर्मेंस। भले ही इसमें एंड्राइड फोन जितनी आजादी तो नहीं मिलती लेकिन फिर भी ये फोन कई यूजर्स की पहली पसंद बना हुआ है। कैमरा इस फोन का USP है। फोन के स्क्रीन को तो हम स्क्रीन गॉर्ड लगा कर प्रोटेक्ट कर लेते हैं लेकिन कैमरा के लिए आज भी कुछ ही लोग प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। क्या आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या हमें अपने फोन पर Camera Lens प्रोटेक्टर का यूज करना चाहिए या नहीं? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं।

iPhone लेंस आमतौर पर सफायर से बना होता है। यह एक ऐसा मटेरियल है जो स्क्रैच-रेसिस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग है। हालांकि, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके iPhone के लेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे बचने के लिए मार्केट में आज कई तरह के कैमरा लेंस प्रोटेक्टर मौजूद हैं लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में 1.5 लाख रुपये के फोन पर इसका यूज करना जरूरी है?

Camera Lens प्रोटेक्टर जरूरी ?

सीधे शब्दों में कहें तो हमें नहीं लगता इसकी सच में जरूरत है। हमने भी काफी समय तक अपने iPhone 13 पर Camera Lens प्रोटेक्टर का यूज किया। जिसकी वजह से

शुरुआत में तो हमें पता नहीं चला कि फोटोज की क्वालिटी में इसकी वजह से फर्क आया है लेकिन कुछ समय बाद हमें फोटोज क्लिक करने के दौरान तस्वीरों में डॉट्स दिखाई देने लगे। इसलिए अगर आप भी ऐसे किसी प्रोटेक्टर का यूज करने का सोच रहे हैं तो अभी अपने प्लान को ड्राप कर दें या कम से कम एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटेक्टर यूज करें।

कैसे चुनें बेस्ट कैमरा प्रोटेक्टर ?

अगर आपने प्लान बना ही लिया है कि कैमरा प्रोटेक्टर का यूज करना है तो सबसे पहले ये जान लें कि 1.5 लाख के फोन पर गलती से भी 150 रुपये वाला कैमरा लेंस प्रोटेक्टर न लगवाएं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। हालांकि इस बात को भी समझ लें जो लेंस कैमरा में मिलते हैं उनकी क्वालिटी के आगे एक्सटर्नल लेंस कुछ भी नहीं हैं।

क्या सच में किसी के याद करने पर आती है हिचकियां, या कोई और है वजह

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 08 फरवरी : अक्सर जब भी हमें हिचकी आती है, तो हम यही सोचते हैं कि कोई खास हमें याद कर रहा है। दिल को खुश करने के लिए ये ख्याल अच्छा है लेकिन इसकी वैज्ञानिक वजह कुछ और ही होती है। असल में हिचकी तब आती है जब हमारी सांसों और पाचन क्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए। हिचकी आने पर इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पर हिचकी कुछ ही देर में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन, अगर यह लंबे समय तक रुके नहीं, तो इसका इलाज जरूरी हो जाता है।

डायाफ्राम एक मांसपेशी है, जो सांस लेने के अंगों को पाचन क्रिया के अंगों से अलग करती है। जब आप सांस लेते हैं, तो आपका डायाफ्राम सिकुड़ता है और फेफड़ों को हवा भरने के लिए जगह मिलती है। जिसके कारण आप सांस ले पाते हैं। सांस छोड़ते समय यह आराम की स्थिति में आ जाता है। जब किसी परेशानी के कारण इस डायाफ्राम में अनैच्छिक सिकुड़न या ऐंठन हो जाए तो, आवाज निकालने वाली नली जिसे वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, वह कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, जिससे 'हिक' या 'हिच' की आवाज आती है। इसी समस्या को ही आम भाषा में हिचकी या अंग्रेजी में हिकप्स और विज्ञान में सिगुलेटस कहते हैं।

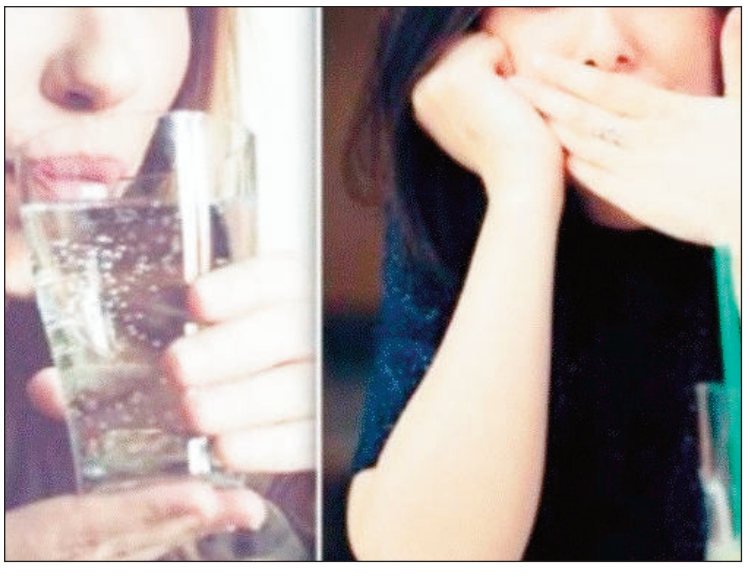

जल्दी-जल्दी हड़बड़ी में खाना , अधिक तीखा या गर्म खाना खा लेना,पेट में गैस होना,बहुत अधिक नर्वस होना, अधिक उत्तेजित होना, कार्बोनेटेड ड्रिंक या सोडा पीना , शराब का सेवन, कोई भी ऐसी क्रिया करना जिसमें आप गलती से हवा निगल जाएं जैसे च्यूइंगम खाना, नर्वस सिस्टम में नसों में हुई किसी परेशानी से लंबे समय तक हिचकी आ सकती है ,किसी दवा का साइड इफेक्ट , ठंडा पानी पिएं जिससे उत्तेजित डायाफ्राम शांत होता है। कुछ सेकंड के लिए सांस रोक कर दोबारा छोड़ें। ध्यान भटकाने की कोशिश करें, या किसी डरावनी बात का जिक्र करें जिससे दिमाग दूसरी तरफ भटक जाए। ऐसा करने से दिमाग हिचकी से ध्यान हटा कर पाचन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के संकेत देता है, जिससे हिचकी रुक जाती है। यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि हिचकी आने पर कोई याद कर रहा है, जिससे इंसान का दिमाग यह सोचने पर जोर डालने लगे कि कौन याद कर सकता है और उसका ध्यान बंट जाए और हिचकी रुक जाए।

महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा के जरिए हो

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून। यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ज्ञापन देकर अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के जरिये होनी चाहिए। डोभाल ने कहा कि उत्तराखंड में असाशकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती एपीआई (एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स) स्कोर के माध्यम से चल रही है। साथ ही अन्य कई महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर एपीआई प्रणाली से भरा जाना प्रस्तावित है। कहा कि राज्य के अशासकीय महाविद्यालयों में 300 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई योग्य अभ्यर्थी नेट और सेट पास कर इन महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर सिफर्.इसलिए आवेदन करने से वंचित हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पीएचडी डिग्री नहीं है। राज्य के बहुत कम विश्वविद्यालय वर्तमान में पीएचडी करवा रहे हैं। ऐसे में यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुसार एपीआई की बाध्यता न होने के बावजूद लिखित परीक्षा के स्थान पर एपीआई आधारित केवल साक्षात्कार के माध्यम से समूह क के इन पदों पर भर्ती करने से योग्य अभ्यर्थी वंचित हो जाते हैं। डोभाल ने कहा कि पड़ोसी राज्य यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के जरिए कराए जाते हैं। जिसमें लिखित परीक्षा 200 व साक्षात्कार के 30 अंक शामिल हैं। उन्होंने इसी तर्ज पर राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा व साक्षात्कार कराने की मांग की है। इससे पारदर्शिता भी सामने आएगी और अभ्यर्थियों के साथ उचित इंसाफ होगा।

रामलला के रंग पर कांग्रेस विधायक की टिप्पणी से विवाद, जमकर हुआ बवाल

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कांग्रेस के एक विधायक ने अयोध्या में रामलला की स्थापित मूर्ति के रंग पर सवाल उठा दिया। कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने बुधवार को विधानसभा में रामलला पर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया। चौहान ने कहा, 'इस (यूसीसी) पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। लेकिन संसीदय कार्यमंत्री (प्रेम चंद्र अग्रवाल) ने कई बार राम मंदिर का संदर्भ दिया कि राम मंदिर बन गया। यह अच्छी बात है। मैंने जितना ग्रंथों में पढ़ा है हमारे भगवान राम सांवले थे, लेकिन इन्होंने उन्हें काला बना दिया, मैं इसे समझ नहीं पा रहा।' उनकी बात का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा, 'आदरणीय स्पीकर मैडम, यह हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य है कि वोट बैंक और ध्रुवीकरण की वजह से यूसीसी (उनके समय में) नहीं लिया गया।' इस पर सत्ता और विपक्ष में जोरदार बहस हुई। अग्रवाल ने कहा, 'इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।' इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्य जय श्री राम के नारे लगाने लगे। यह पहली बार नहीं था जब यूसीसी पर बहस के दौरान राम मंदिर का जिक्र किया गया।

विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए समान नागरिक संहिता पर दूसरे दिन भी बहस हुई। सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने चर्चा में राम मंदिर का भी जिक्र किया और इसे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए उपलब्धि बताया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जब भाषण में राम मंदिर पर बोलने लगे तो कांग्रेस विधायकों को यह कहना पड़ा कि वह यूसीसी के गुण -दोष के बारे में बताएं, राम मंदिर के विषय में नहीं। स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण ने विधायकों को याद दिलाया कि वे बिल पर केंद्रित रहें।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बूथवार बने रणनीति

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए वोटर जागरुकता कार्यक्रम चलाने पर जोर दिया है। बुधवार को सचिवालय में नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा में डॉ पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी की जाएं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान और आयोग के मानकों के अनुरूप स्टेट डिप्लॉयमेंट प्लान बना लिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कार्मिक पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल जैसी अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। लोगों तक इसकी जानकारी अधिकाधिक पहुंचाई जाए। वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बूथ वार रणनीति बनाई जाये। बूथ स्तरीय जागरूकता समूहों को सक्रिय किया जाए। बैठक में संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल, प्रताप शाह, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी नीलेश आनंद भरणे के साथ ही पी रेणुका देवी, डॉ. ललित नारायण मिश्रा, तीरथ पाल, डॉ. सुनिता टम्टा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए।

पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री को दी श्रद्धांजलि

कोटद्वार। यूपी के समय में पूर्व पर्वतीय विकास मंत्री रह चुके यमकेश्वर ब्लाक के कांडी गांव निवासी स्व. चंद्रमोहन सिंह नेगी की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके पैतृक गांव पहुंच उनके स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने कहा कि यमकेश्वर विकास खंड के कांडी गांव में जन्मे स्व. चंद्रमोहन सिंह नेगी ने उत्तराखंड में विकास कार्यों को कराने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होनें बड़े सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में पूर्व प्रमुख कृष्णा रावत, धीर सिंह नेगी, अनुज नेगी, सुरमान नेगी, विनोद कुमार, राजेंद्र सिंह और गोपाल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।

छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

कोटद्वार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी के निर्देशन जनपद पुलिस द्वारा लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर आमजनमानस व छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों व महिला अपराधों पर महत्वपूर्ण जानकारियां देकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज झंडीचौड़ में अध्यनरत छात्र-छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों, महिला सम्बन्धी अपराधों, मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति व गुड-टच, बैड-टच के विषय में जानकारी देकर बचने के उपाय बताये गये। साथ ही सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर तथा व्हाट्सएप आदि) से सम्बन्धित अपराधों, साइबर अपराधों की जानकारी एवं साइबर हेल्पलाईन नंबर-1930, आपात सहायता नम्बर डायल-112, उत्तराखण्ड पुलिस एप के गौरा शक्ति मोड्यूल में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने के बारे में जानकारी दी गयी। पुलिस टीम में महिला उपनिरीक्षक सुमन लता,अपर उपनिरीक्षक कृपाल सिंह व महिला आरक्षी विद्या मेहता शामिल रहे।

राजस्थानी लोकगायक भुट्टे खान मांगनियार ने बिखेरा लोकसंगीत का जादू

देहरादून। राजस्थानी लोकगायक भुट्टे खान मांगनियार एंड ग्रुप ने बुधवार को द प्रेसीडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, दून इंटरनेशनल स्कूल, द दून स्कूल, यूनिवर्सल एकेडमी और द दून गल्र्स स्कूल में मनमोहक राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। स्पिक मैके संस्था द्वारा आयोजित इस प्रस्तुति में राजस्थान के लोककलाकारें ने भगवान कृष्ण को समर्पित भजन से शुरूआत की। केसरिया बलमा पधारो मारे देश.. पर एक जीवंत प्रस्तुति दी गई। कालबेलिया, भवाई, घूमर और तेरहताली जैसे लोक नृत्यों ने कार्यक्रम के आकर्षण को ओर बढ़ा दिया। राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र बाड़मेर से आने वाले भुट्टे खान मंगनियार की उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में एक कोक स्टूडियो में प्रदर्शन और अभूतपूर्व पहल 'धरोहर' शामिल है। जिसके माध्यम से भारत और विदेश के लोक कलाकारों को एक साथ आने का मौका मिला। स्कूली छात्र छात्राओं ने इस प्रस्तुति के दौरान उनसे राजस्थानी फोक संगीत से जुड़े प्रश्न भी पूछे।

उक्रांद का उधूरे मोटर नगर को लेकर धरना

देहरादून। देहरादून में चल रहे विधानसभा सत्र के तीसरे दिन व समस्याओं के खिलाफ प्रदर्शन करने के अपने निर्णय के अंतर्गत उत्तराखंड क्रांति दल ने अधूरे निर्मित मोटर नगर में धरना दिया। धरने में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर पार्टी नेता डॉक्टर शक्तिशैल कपरवाण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से मोटर नगर का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, लाखों रुपया इस अधूरे निर्माण में बर्बाद हो चुका है। 10 वर्षों से भाजपा और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्रियों और शहरी विकास मंत्रियों ने मोटर नगर निर्माण के लिए कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया और न ही नगर निगम बोर्ड के अधिकारियों ने इसकी सुध ली। उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि भाजपा और कांग्रेस के पास विकास का कोई संकल्प नहीं है, इसलिए वे महानगर के कार्यों से भी मुंह मोड़ रहे हैं। मौके पर उन्होंने आगामी चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की। धरना प्रदर्शन करने वालों में जगदीपक सिंह रावत,गोविंद डंडरियाल ,मुजीब नैथानी, प्रवेश चंद्र नवानी,अनुसूया प्रसाद सेमवाल, प्रवेंद्र रावत , पुष्कर सिंह रावत ,प्रवेश नवानी ,पुष्कर रावत ,सत्य प्रकाश भारद्वाज, राजेंद्र प्रसाद पंत ,सर्वेंद्र काला भारत मोहन काला ,सत्यपाल सिंह नेगी और प्रकाश बमराड़ा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।

देश रत्न सम्मान से नवाजे गए डा. मनीष

उत्तरकाशी। गाजणा पट्टी के ब्रह्मपुरी गांव निवासी व दंत चिकित्सक डा. मनीष भट्ट को देश रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत युवा वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदान किया है। पिछले 16 वर्षों से अधिक समय से डॉ. भट्ट चिकित्सा पेशे से जुड़े हैं।

संक्षप्ति खबरें

छात्राओं को कॅरियर से जुड़ी तमाम जानकारियां दीं

रुद्रपुर। निकटवर्ती जगदीशपुर गांव के राजकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के कॅरियर और गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने छात्राओं को कॅरियर से जुड़ी जिज्ञासाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। निकटवर्ती जगदीशपुर गांव स्तिथ राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को प्रधानाध्यापक विजय शंकर के नेतृत्व में छात्राओं के कॅरियर और गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढीमरी ब्लॉक की प्रधानाध्यापक श्रद्धा रानी ने छात्राओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कॅरियर से जुड़ी तमाम जानकारियां दीं। इस दौरान छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए। कार्यक्रम में जय प्रकाश सिंह, धर्मवीर सिंह, राजकुमार जोशी, मंजू जोशी, शोभा रानी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं को लेकर निकाली जागरूकता रैली

काशीपुर। राजकीय पॉलिटेक्निक की एनएसएस इकाई के सात दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन बुधवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमाऊं कॉलोनी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कचनाल गाजी में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर जन जागरूकता रैली निकाली गई। स्वयंसेवियों ने आम लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर भी बनाए। साथ ही संस्था परिसर और आसपास सफाई कार्य किया। बौद्धिक सत्र में डॉ. शोएब ने स्वयंसेवियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी राजीव यादव, डॉ. ओपी सिंह, मनमोहन आदि मौजूद रहे।

सडक़ हादसे का आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त

काशीपुर। एसीजे प्रथम की अदालत ने सडक़ हादसे के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। ग्राम रायपुर खुर्द निवासी कश्मीर सिंह ने 20 जुलाई 2016 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र गुरवीर सिंह व भतीजा मंदीप पुत्र सुखदेव सिंह बाइक पर कुंडेश्वरी से अपने घर आ रहे थे। आरटीओ ऑफिस के पास पीछे से आए ट्रक ने लापरवाही से वाहन चलाकर उनके पुत्र की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल गुरवीर सिंह को मुरादाबाद रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक चालक मशकूर अली पुत्र हशमत अली के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। केस की सुनवाई एसीजे प्रथम दीप्ति पंत की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता समर्थ विक्रम ने की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी ट्रक चालक को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

कांग्रेस के कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष बने नितिन

हरिद्वार। कांग्रेस ने नितिन यादव को मायापुर का कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। हरिद्वार महानगर अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी, कार्यकारी अध्यक्ष अमन गर्ग, मुरली मनोहर ने कहा नितिन यादव को कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। स्वागत करने वालों में युवा विधानसभा अध्यक्ष तुषार कपिल, सेवादल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष आर्यन राठौर, ओम पहलवान, शुभम जोशी, ऋषभ वशिष्ठ, करण सिंह राणा, मोनू राजपूत, सतेंद्र दुबे, हरिनारायण, संजय राजपूत, कुश पाण्डे आदि मौजूद रहे।

जापान के वैज्ञानिकों ने सीएनजी बायोगैस संयंत्र का भ्रमण किया

हरिद्वार। जापान के ग्रीन इनोवेशन डेवलपमेंट सेंटर के प्रमुख इंजीनियर माशाको टनका और उनके सहयोगी कैंटो मुराता, एयर वाटर इंडिया के निदेशक कजुमा होगूची और बिजनेसमैन अतसूसी ईशोनो ने बुधवार को कृष्णायन गोशाला सीएनजी बायोगैस संयंत्र का भ्रमण किया। माशाको ने गोशाला के उपक्रम की सराहना करते हुए कहा कि गाय के गोबर से बनने वाली बायोगैस की भविष्य में अपार संभावनाएं है। संयंत्र से 400 किलोग्राम प्रतिदिन बायोगैस बन रही है, यह बड़ी उपलब्धि है। इस गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट खाद और संयंत्र में बनाये जा रहे विभिन्न प्रकार के कीटाणु और फफूंदीनाशक जैविक खाद के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर स्वामी अनंतानंद, एनालिस्ट डॉ. निवेदिता, जैविक खाद वैज्ञानिक राजीव योगी, कुलवीर सिंह आदि मौजूद थे।

जीजीआईसी ज्वालापुर को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

हरिद्वार। दिल्ली में यूनेस्को और जल मंत्रालय के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में जीजीआईसी ज्वालापुर को बेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा यूनेस्को के डायरेक्टर टिम कुर्टिस ने विद्यालय की प्रधानाचार्य पूनम राना को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य पूनम राना ने बताया कि उत्तराखंड से पीएमश्री योजना में जीजीआईसी ज्वालापुर को यह पुरस्कार मिला। जिससे पूरे विद्यालय परिवार में खुशी की लहर है। कैबिनेट मंत्री ने इस पुरस्कार के लिए विद्यालय की छात्राओं, शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य के प्रयासों की प्रशंसा भी की। मंत्री ने गंगा स्वछता, पॉलिथीन उन्मूलन, विद्यालय में चल रही एनएसएस की इकाई के जल संरक्षण संबंधी प्रयासों की भी सराहना की। भविष्य में और अधिक समर्पित भाव से चेतना एवं जागरुकता फैलाने का आह्वान किया। विद्यालय की इस उपलब्धि पर निवर्तमान निदेशक सीमा जौनसारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट, जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी केके गुप्ता, खंड शिक्षा अधिकारी स्वराज तोमर ने पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी हैं।

सीवर की गंदगी पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

ऋषिकेश। हरिपुरकला में सीवर लाइन की समस्या को लेकर ग्रामीणों का पारा चढ़ गया। उन्होंने पेयजल निगम कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। शीघ्र सीवर लाइन को दुरुस्त नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बुधवार को हरिपुरकला के ग्रामीण प्रधान गीताजंलि जखमोला की अगुवाई में पेयजल निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शन कर जगह-जगह बंद सीवर लाइन का दूषित पानी सडक़ों पर बहने की समस्या को लेकर नारेबाजी की। प्रधान ने कहा कि क्षेत्र में पेयजल निगम की सीवर लाइन साफ-सफाई के अभाव में बंद हो चुकी है। सीवर का दूषित पानी न सिर्फ सडक़ों पर बह रहा है, बल्कि वह गंगा तक भी पहुंच रहा है। कई दफा शिकायत के बावजूद अधिकारी समस्या के समाधान को तैयार नहीं हैं। अधिशासी अभियंता मीनाक्षी मित्तल ने गुस्साए ग्रामीणों को एक माह के भीतर सीवर लाइन की मरम्मत और सफाई कराने का भरोसा दिलाया। अधिशासी अभियंता के आश्वासन पर प्रदर्शनकारी शांत हुए। प्रदर्शनकारियों में भाजपा नेता मनोज जखमोला, राजेश लखेड़ा, मनोज शर्मा, धर्मेंद्र ग्वाड़ी, सुरेंद्र रयाल, अंकित बहुखंडी, अनुज रावत, दीपिका लखेड़ा, सुधा भट्ट, सूरज तिवारी, अमृत पाल, सतीश ध्यानी, संजय रावत, हरीश शर्मा, दिलावर बिष्ट, सत्य प्रकाश, खुशी जोशी, लक्ष्मी मिश्रा, अमरजीत आदि रहे।

क्या आप जानते हैं ज्यादा सोचना भी है नुकसानदायक

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 फ़रवरी , अगर आप किसी भी बात को लेकर बहुत अधिक सोचने लगते हैं और बार-बार उसे सोचकर परेशान भी होते हैं तो ये खबर पढ़ लीजिये । आमतौर पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे आपके नियंत्रण के बाहर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी आप इनके बारे में सोचकर तनावग्रस्त और चिंताग्रस्त होते रहते हैं। क्या आप जानते हैं आपके साथ ऐसा क्यों होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि विशेषज्ञ इस विषय में क्या राय रखते हैं।

ओवर थिंकिंग के प्रमुख कारण -

हर व्यक्ति का स्वभाव अलग-अलग होता है। जब आपका स्वभाव दूसरों को प्रसन्न करने वाला होता है, तब दूसरों की प्रतिक्रियाएं आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप खुद को खुश रखने की जगह दूसरों की खुशियों के बारे में अधिक सोचने लगते हैं। दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में आप क्षमता से ज्यादा काम करने लगते हैं, इसका असर आपके शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी पड़ता है। कई बार हम अपनी जरूरतों, भावनाओं और खुशियों के बारे में सोचना भूल जाते हैं। दरअसल, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम ओवरथिंकिंग के शिकार होते हैं। इन्हें ठीक करने की ओर कदम बढ़ाकर हम खुद के लिए खुश होना सीख सकते हैं।

शर्मिंदगी का डर

जब हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमें शर्मिंदगी का डर भी ज्यादा होता है। अपनी छोटी सी गलती या भूल को भी हम बड़ा मान बैठते हैं और उसके बारे में लगातार सोचते हैं। यह आपके तनाव का कारण बन सकता है। इसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है।

खुद की इमेज खराब होने का भय

जब हम किसी बात को लेकर ज्यादा सोचते हैं तो हम अपनी इमेज को लेकर भी ज्यादा सर्तक हो जाते हैं। हम डरे रहते हैं कि दूसरे हमें नकारात्मक तरीके से देखेंगे। ऐसे में हम सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए ज्यादा कोशिश करने लगते हैं और अंत में खुद ही परेशान भी होते हैं। इसलिए दूसरों को दुखी किए बिना, खुद के लिए जीना सीखें।

खुद को दोषी न ठहराएं

अतीत के अनुभवों का बोझ लेकर घूमना छोड़ दें, जो बातें आपके बस में नहीं है उनके बारे में सोचना और खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद करें। आज में जीना सीखें, जो वक्त है उसे खूबसूरत बनाने पर ध्यान दें। ध्यान रखें कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे सीखें, इन्हें बोझ न बनाएं।

खुद पर विश्वास रखें

खुद पर विश्वास रखकर आप दुनिया जीत सकते हैं। आपका आत्मविश्वास ही आपको सभी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए काफी है। दरअसल, आघात और कटु अनुभव आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं, जब आप इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं तो आपकी क्षमताएं कम होने लगती हैं। ऐसे में खुद पर विश्वास रखें। यही इसी स्थिति से आपको बाहर निकालेगा।

भारतीयों के बीच क्यों पॉपुलर है शादी ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 फ़रवरी , आंकड़े बताते हैं सालाना लाखों की तादाद में लोग शादी के बंधन बंधते हैं, जो देश की सांस्कृतिक विविधता और रीति-रिवाजों की रंगीन तस्वीर पेश करते हैं. हर जाति, धर्म और क्षेत्र की कहानी अलग है. हर शादी समारोह अपनी परंपराओं का अनूठा संगीत गाता है. पारंपरिक विवाह के साथ-साथ, लव मैरिज का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. युवा पीढ़ी अपने जीवनसाथी का चुनाव खुद कर रहे हैं. इंटरकास्ट और इंटरफेथ शादियां भी बढ़ रही हैं. हालांकि, इन बदलावों के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं.

आइए भारत में शादी की संस्कृति में गहराई से उतरने की कोशिश करते हैं. इसके महत्व के बारें में बात करते हैं और जानते हैं ये चलन कैसे आगे बढ़ रहा है.

कितनी शादी होती है भारत में?

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है. हालांकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के आंकड़ों में थोड़ा अंतर है. ग्रामीण क्षेत्रों में शादी करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है. वहीं शहर में शिक्षा के बढ़ते महत्व के कारण शादी की उम्र बढ़ रही है.आंकड़ों के अनुसार, साल 2020 में शादीशुदा भारतीयों की संख्या 45 फीसदी से ज्यादा थी. इसमें 30 से 34 साल के बीच के पुरुष और महिलाओं की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा था. इसके अलावा 25 से 29 साल के बीच के विवाहित भारतीयों की आबादी का हिस्सा पांच फीसदी से अधिक था.

कितना बड़ा है भारत में शादी-विवाह उद्योग ?

शादी-विवाह उद्योग देश में चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है. बहुत से लोग शादी को यादगार बनाने के लिए खुले हाथ से खर्च करते हैं. भारत में शादी समारोह पर हर साल करीब 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं. साल 2022 में नवंबर

और दिसंबर के बीच भारतीयों ने शादियों पर अनुमानित 3.75 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे. ये आंकड़ा पिछले साल से 25 फीसदी ज्यादा है. 2021 में इसी समय तीन लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए. CAIT की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 23 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच देश में 38 लाख शादियां हुईं. इससे लगभग 4.74 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने का अनुमान है. यानी कि पिछले साल से 1 लाख करोड़ ज्यादा खर्च हुआ।

शरीर में दर्द है तो आप जमीन पर सोना शुरू कर दें

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 फ़रवरी , आजकल की लाइफस्टाइल में लोग अपने बेडरूम में मोटे से मोटा गद्दा का इस्तेमाल करते हैं. जमीन पर सोना तो अब पुराने ज़माने की बात हो गई है. लोग अपने बेड से किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है. दिनभर की भागमभाग और थकावट के बाद आपको भी लगता ही होगा कि कैसे भी अपने बिस्तर में घुसकर सुकून की नींद ले. हालांकि आजकल ज्यादातर लोग इसी वजह से पीठ और कमर के दर्द से परेशान रहते हैं. सबसे पहले एक पतली सी चटाई या कारपेट लें. अगर आपको असुविधा हो रही है तो चटाई पर कोई पतला सा गद्दा बिछा लें. इससे हड्डियों का अलाइनमेंट ठीक रहता है.

अगर आपको काफी ज्यादा पीठ में दर्द होता है तो जमीन पर सोते वक्त पीठ के बल ही सोएं. इससे रीढ़ की हड्डी को काफी ज्यादा आराम मिलेगा. जमीन पर जब आप सोने की आदत बनाते हैं तो पतले तकिए का ही इस्तेमाल करें . इससे आपकी आदत भी बनेगी और बिना तकिया सोने से सांस लेने की परेशानी भी दूर रहेगी.

जमीन पर सोने के लिए मुलायम गद्दे का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाएगी.

जमीन पर सोने के अनोखे फायदे

रीढ़ की हड्डी रहेगी एकदम ठीक

जमीन पर सोने से रीढ़ की हड्डी में दर्द और अकड़न कम होती है. जब आप गद्देदार गद्दे पर सोते हैं तो रीढ़ की हड्डी अकड़ जाती है. जिसका सीधा असर दिमाग पर पड़ता है. रीढ़ की हड्डी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है. इसका सीधा कनेक्शन ब्रेन से जुड़ा हुआ है.

मांसपेशियों को मिलता है आराम

जमीन पर सोने से कंधे और कूल्हे में होने वाले दर्द से बहुत आराम मिलता है. इससे पीठ दर्द, कंधे और गर्दन की दर्द में राहत मिलती है.

पीठ दर्द में राहत

जो लोग जमीन पर सोते हैं उनका पोस्चर ठीक रहता है और कमर दर्द भी कम हो जाती है.

शरीर का टेंपरेचर होता है कम

जमीन पर सोने से शरीर का टेंपरेचर हो जाता है कम. वहीं बेड पर सोने से शरीर की गर्मी बढ़ जाती है. जिससे बॉडी का टेंपरेचर बढ़ने लगता है.

ब्लड सर्कुलेशन रहता है ठीक

जमीन पर सोने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है. जिसके कारण मांसपेशियों को आराम मिलता है और तनाव कम हो जाता है.

बॉस के कॉल पर तुरंत बजेगी रिंग, ये है सेटिंग

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 फ़रवरी , अगर फोन साइलेंट या डीएनडी पर सेट है और किसी इंपोर्टेंट व्यक्ति का फोन आ रहा तो ये अक्सर मिस हो जाती है। कभी-कभी वे कॉल पेरेंट्स के भी हो सकते हैं और रिसीव ना करने पर वो परेशान हो सकते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपने स्मार्टफोन की सेटिंग में थोड़ी बदलाव कर लें। जानकारी के लिए बता दें, एक छोटी सी सेटिंग करके आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आपकी कॉल भी छूट जाती है तो यहां हम कुछ टिप्स बताए हैं, जिससे आप अपने फोन को साइलेंट मोड में रखते हुए भी इंपोर्टेंट पर्सन की कॉल पर रिंग की सेटिंग कर सकती हैं। फैमिली, फ्रेंड या बॉस आदि की कॉल ना छूटे, इसके लिए फोन में ये सेटिंग जरूर करें।

साइलेंट या DND मोड में इंपोर्टेंट कॉल पर रिंग की सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाएं।

यहां जाकर वो नंबर चुनें जिसे आप कॉल आने पर रिंग चाहती हैं।इसके बाद उन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर स्टार आइकन टैप कर दें।ये कॉन्टैक्ट Favourite या Starred Contact बनाने के बाद फोन की सेटिंग ऐप ओपन करें।

यहां से आप DND या Sound सेटिंग्स पर जाएं।आपको यहां पर नोटिफाई अबाउट कॉल्स का ऑप्शन दिखेगा, उसपर टैप करें।अब, आप

उन Starred Contact को चुन सकते हैं। (लोकेशन ट्रैक ऐप्स)बस, ये सेटिंग पूरी करने के बाद साइलेंट या DND मोड होने पर भी इन कॉन्टैक्ट नंबर से कॉल आने पर रिंग बजने लगेगी।

अक्सर लोग अपने फोन को साइलेंट करके भूल जाते हैं। इमरजेंसी की हालत में भी जरुरी कॉल्स रिसीव नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये सेटिंग आपके काफी काम आ सकती है। मान लीजिए आप फोन साइलेंट करके कहीं रख कर और भूल गए, तो ऐसी स्थिति में रिंग के जरीए तुरंत आपका फोन मिल सकता है। लेकिन साइलेंट मोड की वजह से आपको कॉल का पता नहीं चलेगा।

10 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में वक्त बिताने पर हाथ से गई नौकरी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 08 फरवरी : आज के समय में नौकरी मिलना बेहद मुश्किल है. ऐसे में अगर आपको नौकरी मिलने के 3 दिन बाद ही जॉब को छोड़ना पड़ जाये, तो यकीनन हैरानी होना लाजिमी है. इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं. कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, जो अच्छे ऑफर और ज्यादा सैलरी के चक्कर में जल्दी-जल्दी नौकरियां बदलते रहते हैं. वहीं कई बार लोग काम के प्रेशर और बॉस से परेशान होने के कारण भी नौकरी छोड़ देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही मामला इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक महिला नौकरी मिलने के 3 बाद ही उसे खोने के पीछे की वजह बताते हुए अपना दर्द बयां कर रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट में बताया जा रहा है कि, कैसे एक महिला कर्मचारी ने नौकरी मिलने के तीन बाद सिर्फ इसलिए जॉब छोड़ दी, क्योंकि बॉस ने उससे ऐसी-ऐसी बातें कहीं, जिससे तंग आकर उसने नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया. रेडिट पर महिला ने अपनी आपबीती बताते हुए लोगों से ये भी पूछा है कि, उसने कुछ गलत तो नहीं किया न? महिला ने बताया कि, बीते सोमवार उसने कंपनी ज्वाइन की थी. इसके एक दिन बाद ही यानि की बुधवार को बॉस ने उसे जॉब छोड़ने के लिए कह दिया।

महिला के मुताबिक, बॉस के कहने से पहले ही उसने खुद ही रिजाइन दे दिया था. महिला ने बताया कि उसने किस वजह से इतनी जल्दी में ये फैसला लिया. महिला ने पोस्ट में बताया कि, उसका बॉस उसे डांटता था और कहता था कि, एक तो तुम काम नहीं करती हो और ऊपर से टॉयलेट में 10 मिनट से ज्यादा टाइम बिताती हो. यही नहीं बॉस ने महिला कर्मचारी को डांटते हुए यह तक कह दिया कि, वो मानसिक तौर पर बीमार है. महिला ने बताया कि, बॉस द्वारा ऐसा कहने पर उसे बहुत बुरा लगा और उसे लगा कि भला कोई भी बॉस अपने कर्मचारी से इस तरह की बात कैसे कर सकता है।

महिला ने पोस्ट में आगे बताया कि, बॉस का कहना था कि, वो काम नहीं करती है, असल में मुझे बॉस ने कभी कोई काम दिया ही नहीं, बल्कि ऑफिस में ही मेरा एक कलीग मुझे काम दिया करता था, जिसे मैं पूरा करने की कोशिश कर रही थी. इसके साथ ही महिला ने बॉस द्वारा कही गई टॉयलेट में 10 मिनट से ज्यादा समय बिताने वाली बात पर कहा कि, उसे कब्ज था, जिसकी वजह से उसे बार-बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था, लेकिन बॉस ने महिला की परेशानी समझने की कोशिश ही नहीं की. ऐसा महिल का कहना था. उल्टा बॉस ने महिला का यह कह कर शांत कर दिया कि, तुम मुझसे बहस कर रही हो।

पोस्ट में आगे बताया गया है कि, बॉस ने महिला कर्मचारी से कहा कि, वो काम करने लायक नहीं है और अब वो जॉब को लेकर कल अपना रवैया बताएगा. इस पर महिला ने बॉस को कहा कि, वो इसी वक्त इस्तीफा दे रही है और यही वजह थी कि, महिला ने बॉस की बातों से तंग आकर तीन दिन में नौकरी छोड़ दी।

Internet पर कहीं आपकी तस्वीर जाये मिस यूज ?

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 फ़रवरी , इंटरनेट का यूज तो आज हम सभी करते हैं। एक तरफ जहां इसने कई कामों को आसान किया है वहीं नए-नए खतरों को भी जन्म दिया है। इंटरनेट पर कहां, कब और कैसे कुछ लीक हो जाए कहना काफी मुश्किल है। हाल ही में डार्क वेब पर 75 करोड़ टेलीकॉम यूजर्स का डाटा लीक हुआ था। ऐसे में सवाल ये है कि हम कैसे पता करें कि कहीं हमारा डाटा तो ऑनलाइन लीक नहीं हो गया? तो बता दें इसे जानने के कई तरीके हैं। वहीं आज हम हम आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि इंटरनेट पर कहां-कहां आपकी तस्वीरें मौजूद हैं। जी हां, आप इस बात का पता मिनटों में लगा सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में..

क्या है इस टूल का नाम

दरअसल आप एक ऑनलाइन टूल यानी PimEyes का यूज करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि कहां-कहां इंटरनेट पर आपकी तस्वीरें मौजूद हैं। यह टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इस बात की जानकारी देता है। आइये जानते हैं कैसे काम करता है ये ऑनलाइन टूल

कैसे काम करता है ये टूल ?

यह टूल दुनिया भर में मौजूद आपकी या आपके किसी हमशक्ल को मिनटों में खोज सकता है। AI का यूज करके ये आपका इंटरनेट पर मौजूद विजुअल डाटा कलेक्ट करता है जिससे आप किसी भी फोटो को अपलोड करके उसके जैसी फोटोज मिनटों में देख सकते हैं। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपकी फोटो इंटरनेट पर कहां-कहां मौजूद हैं। हमने भी इस टूल का यूज करके अपने एक साथी की तस्वीर को सर्च बॉक्स में डाला जिसके बाद वेबसाइट ने चौंकाने वाले रिजल्ट दिए। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें।

कैसे करें इस टूल का यूज ?

इसका यूज करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउज़र पर PimEyes सर्च करें।

इसके बाद सबसे पहले लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएं।

यहां आपको फोटो अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा

इस पर क्लिक करें।अब गैलरी से किसी भी फोटो को सेलेक्ट करें जिसे आप ऑनलाइन ढूंढ़ना चाहते हैं।

इतना करते ही सर्च बटन प्रेस करें।इधर अब आपको अपनी सभी तस्वीरें दिख जएंगी।

सावधान! क्यूआर कोड से हो रहा साइबर फ्रॉड

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट , 8 फ़रवरी , दुनिया भर में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे है। आपने फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग की खबरें तो सुनी ही होगी। लेकिन अब दुनिया में क्लिशंग के मामले भी तेजी से बढ़ रहे है। अब जालसाज नकली क्यूआर कोड के माध्यम से यूजर्स को ठग रहे है। इस तरह के अपराध में न सिर्फ पैसे से जुड़ी धोखाधड़ी होती है बल्कि यूजर्स के फोन की हैकिंग भी की जा रही है।

साल 2023 में बढ़ी यूपीआई स्कैम की वारदात

बीते साल यूपीआई से जुड़े मामले कई ज्यादा बढ़ गए हैं। 2023 में यूपीआई फ्रॉड की शिकायत 30 हजार से ज्यादा हो गई हैं। साल 2022 में इस तरह के मामलों की संख्या 15 हजार थी। यूपीआई संबंधित मामले में ज्यादातर क्यू आर कोड से जुड़े हुए हैं।

इंस्टाग्राम और वाट्सएप फ्रॉड के बड़े माध्यम

साइबर सेल के अधिकारी बताते है कि ये स्कैमर वाट्सएप या इंस्टाग्राम पर टारगेट को क्यूआर कोड भेजते है। फिर पीड़ित कैशबैक के लालच में इस स्कैनर को अपने फोन से सीधे स्कैन करता है। साथ ही उसमें राशि डालकर पिन दर्ज करता है। इसके बाद स्कैमर टारगेट के बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है। आखिर में स्कैमर टारगेट के खाते से बड़ी रकम खाली कर देता है।

पैसे ही नहीं डेटा भी चुराते है स्कैमर

साइबर सुरक्षा अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस स्कैमर द्वारा भेजे क्यूआर कोड को स्कैन करना आपके फोन का पिछला दरवाजा खोलने जैसा है। यूजर अनजाने में मालवेयर को भी डाउनलोड कर सकता है। इससे यूजर का फोन पूरी तरह हैक हो सकता है। स्कैमर द्वारा फोन पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जाती है। यूजर को इस बात पर जोर देना चाहिए की पेमेंट रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन दर्ज नहीं किया जाता है।

दुनिया भर में बढ़ रहे मामले

भारत में पिछले कुछ महीनो में 40 व्यापारियों को सायबर ठगों ने ठगा और उन्हें लाखों का चूना लगाया है। ये स्कैमर साउंड बॉक्स इंस्टॉलर बन कर आते है और इन साउंड बॉक्स में खास तरह की सेटिंग कर व्यापारियों को चूना लगाते हैं। नए तरह के क्यूआर कोड स्कैम में ड्राइवरों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें पार्किंग के लिए ड्राइवरों को क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए किया जा रहा है। दरअसल, ये स्कैमर पार्किंग में लगे क्यूआर कोड के स्टीकर बदल देते है। ड्राइवरों के स्कैन करते ही ये स्कैमर इनके यूपीआई समेत बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड तक पहुँच जाते है।

ऑनलाइन चोरी हुई रकम को वापस लाना बेहद कठिन

साइबर सेल के एक अधिकारी का कहना है कि इस तरह के मामले में ऑनलाइन चोरी हुए पैसों को वापस लाना बेहद कठिन है। इस तरह के मामले में चोरी हुए पैसों को ब्लॉक करने की कोशिश करते है। लेकिन शातिर स्कैमर एफआईआर होने से पहले ही दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर कर लेते है।

कुत्तों की जगह गायों को यूनिट में शामिल करेगी पुलिस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 08 फरवरी : अपराधियों को ढूंढने के लिए पुलिस कुत्तों का इस्तेमाल करती है। कुत्तों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में वे प्रशासन की मदद करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुत्तों की जगह कोई और जानवर भी ये काम कर सकता है? वो भी बिना ट्रेनिंग के। मामला है अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना का, जहां एक भगोड़े की तलाश में पुलिस काफी समय से लगी हुई थी। पुलिस ने हर जगह उस अपराधी को खोजने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सकी।

आपको जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय से अपराधी को खोज रही पुलिस का काम कुछ गायों ने आसान कर दिया। 'टाइम्स नाऊ' की खबर के मुताबिक, अपराधी का पीछा कर रहे आरोपी को जब कहीं जगह नहीं मिली तो वो खेत में जा छिपा। ट्रैफिक स्टॉप से भागा अपराधी सीधे जाकर घास फूस में जा घुसा। एक प्रेस रिलीज में अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध ने डीप गैप में यूएस 421 और यूएस 221 के एरिया में अपना वाहन छोड़ दिया और एक ऐसे इलाके में भाग गया, जो विकसित नहीं था। उसकी तेज स्पीड और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हमारे अधिकारी ये देख नहीं सके कि वो भागा कहां है।

बताते चलें कि शख्स की पहचान 34 वर्षीय जोशुआ रसेल मिंटन के तौर पर हुई है। वो पुलिस से बच निकलने की फिराक में खेत में जा छिपा था लेकिन लंबे समय तक वहां रह नहीं सका क्योंकि नाराज गायों ने उसे अपने इलाके में टिकने ही नहीं दिया। जैसे ही अधिकारियों ने उस इलाके में खोजबीन शुरू की, वहां की गाय मानो उनका स्वागत करने लगीं। जाहिर तौर पर गाय भी संदिग्ध को अपने इलाके से बाहर निकलवाना चाहती थीं। उन्होंने एक तरह से छुपे हुए संदिग्ध को निकालने में अधिकारियों की मदद की। जब गायों ने पुलिस की मदद की तो पुलिस के अधिकारी भी कुत्तों की जगह गायों को ट्रेनिंग देने लिए कहा ?

पौड़ी : मासूमों को निवाला बनाने वाले आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी 08 फरवरी : उत्तराखंड के पौड़ी जिले में गुलदार के आतंक के चलते कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। यहां तीन फरवरी को गुलदार ने दो बच्चों को अपना निवाला बना लिया। हालात ये हो गए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल बंद करने पड़ गए हैं। गुलदार के बढ़ते आतंक को देखते हुए प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव डॉ. समीर सिन्हा ने आदमखोर गुलदार को मारने के आदेश दिए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी को दिए आदेश में कहा गया कि विशेष रूप से छोटे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए चिह्नित गुलदार को अंतिम विकल्प के रूप में मारने के आदेश दिए गए हैं।

गुलदार के हमले को लेकर डीएफओ ने प्रमुख वन संरक्षक को रिपोर्ट भेजी थी, जिसमे बताया गया कि दो बच्चों को मारने वाला गुलदार अब भी घटनास्थल के पास दिखाई दे रहा है। गुलदार को न तो पकड़ा जा सका है और न ही उसे ट्रैंक्यूलाइज किया जा सका है। गुलदार मानव जीवन के लिए खतरा हो गया है। प्रमुख वन संरक्षक की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि जन सुरक्षा को देखते हुए गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने या ट्रैंक्युलाइज करने के सभी प्रयास किए जाएं। अगर इसके बाद भी पकड़ में नहीं आए तो गुलदार को मार दिया जाए।

यह आदेश केवल चिह्नित गुलदार के लिए प्रभावी होगा। गुलदार को मारने की यह आज्ञा एक महीने तक वैध रहेगी, जो इस अवधि के बाद खुद समाप्त हो जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया कि क्षेत्र में ट्रैप कैमरा और पीआईपी के माध्यम से गुलदार की उपस्थिति की निगरानी की जाए। ड्रोन से भी क्षेत्र में निगरानी की जाए।

बता दें कि गुलदार ग्राम ग्वाड़ और ग्लास हाउस श्रीनगर में पिछले दो दिन में दो बच्चों को मार चुका है। तीन फरवरी को गुलदार ने ग्राम ग्वाड़ पोस्ट खिर्सू निवासी 11 साल के अंकित को मार दिया था। जबकि चार फरवरी को ग्लास हाउस रोड़ निवासी चार साल के अयान अंसारी को गुलदार घर के आंगन से उठा ले गया। बच्चे का शव घर से 20 मीटर दूर झाड़ियों से बरामद किया गया था।

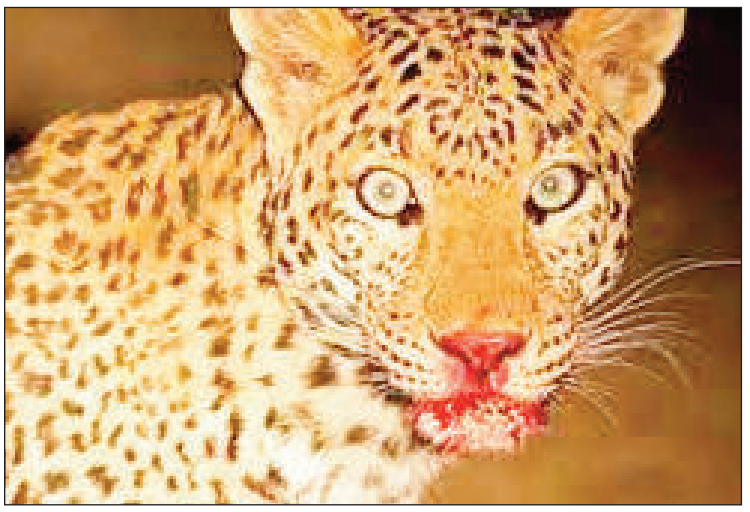

अजब गजब : यहां पूरी जिंदगी में सिर्फ 1 दिन नहाती हैं लड़कियां

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 08 फरवरी : भारत ही नहीं दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के अनोखे रिवाज चर्चा की विषय बने रहते हैं. कइयों पर तो भरोसा करना भी मुश्किल होता है. ऐसे ही कई परंपरा निभाई जाती है अफ्रीका की हिम्बा जनजातियों के बीच. जहां, लोग मेहमानों के साथ बीवी को सुलाते है और यहां लड़कियां सिर्फ एक ही दिन नहाती हैं वो भी अपनी शादी के रोज. आइये जानते हैं क्या है इसका कारण और क्या है हिंबा जनजाति अन्य परंपरा..हिंबा जनजाति अफ्रीकी देश नामीबिया के कुनैन प्रांत में निवास करती है. ये इलाका दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में से एक है. इसी कारण हिंबा जनजाति में कई ऐसी परंपराएं और रीति-रिवाज होते हैं जो लोगों को अचरज में डालते हैं. इनकी कई परंपराएं पानी के इस्तेमाल पर निर्भर होती हैं.

हिंबा जनजाति की लड़कियों के केवल एक ही दिन नहाने की परंपरा है वो भी शादी के दिन. ऐसा वहां पानी की कमी के कारण किया जाता है. हालांकि, सारी उम्र न नहीने के बाद भी इनकी महिलाओं के शरीर से बदबू नहीं आती. इसके लिए वो एक खास किस्म का पेस्ट का उपयोग करती हैं जो तेल में एक खनिज की धूल मिलाकर तैयार किया जाता है.यहां महिलाएं जिस लेप का उपयोग करती हैं वो सिर्फ गंध मिटना के लिए ही नहीं बल्की कई और काम आता है. ये खास लेप इन महिलाओं को धूप से बचाने के साथ ही कीट पतंगों से त्वचा की रक्षा करता है. इससे महिलाओं के चेहरे पर निखार आता है जिससे इनका रंग हल्का दिखाई देता है. हिंबा जनजाति महिलाएं जड़ी बूटियों का धुआं अपने शरीर में लगाती हैं. यहां के लोग मेहमानों की आवभगत के लिए अपनी बीवी के साथ सेक्स करने की छूट देते हैं. इस दौरान घर का पुरुष या तो दूसरे कमरे में सोता है या फिर घर के बाहर. हिंबा जनजाति में पुरुषों और महिलाओं को अन्य लोगों के साथ एक से अधिक संबंध बनाने की आजादी है.

क्या काला चश्मा पहनने से नहीं फैलता कंजंक्टिवाइटिस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट 08 फरवरी : कंजंक्टिवाइटिस के मामले इन दिनों देशभर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसे आमतौर पर पिंक आई या आई फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। आंखों में होने वाला यह संक्रमण हर लगभग हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि, युवाओं में इसके मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कंजंक्टिवाइटिस होने पर आंखों में रेडनेस, जलन, खुजली, डिस्चार्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

कंजंक्टिवाइटिस होने पर अक्सर लोगों को गहरे रंग का धूप का चश्मा पहनने की सलाह दी जाती है, लेकिन क्या सच में सिर्फ काला चश्मा कंजंक्टिवाइटिस को रोक सकता है। अगर नहीं, तो कंजंक्टिवाइटिस होने पर काला चश्मा क्यों पहना जाता है। आज इस आर्टिकल में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे, तो आइए जानते हैं आई फ्लू होने पर काला चश्मा पहनने की वजह-

कंजंक्टिवाइटिस होने पर यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धूप का चश्मा इस संक्रमण के प्रसार को नहीं रोकता है। जब किसी को कंजंक्टिवाइटिस होता है, तो उनकी आंखें

प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। ऐसे में धूप का चश्मा पहनने से रोशनी से होने वाली असुविधा को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि, संक्रमण अभी भी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क से या उनके संपर्क में आई दूषित वस्तुओं को छूने से फैल सकता है।

कई लोगों का ऐसा मानना है कि कंजंक्टिवाइटिस होने पर काला चश्मा इसलिए पहना जाता है, क्योंकि संक्रमित की आंखों में देखने भर से कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। हालांकि, यह एक मिथक है कि सिर्फ किसी को देखने से यह इन्फेक्शन फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति को देखने से कंजंक्टिवाइटिस नहीं फैलता है। इस दौरान धूप का चश्मा इसलिए भी लगाया जाता है, ताकि लगातार आंखों को रगड़ने की संभावना को कम किया जा सके, जो संभावित रूप से संक्रमण फैला सकता है।

इन सबके अलावा काला चश्मा धूल के कणों, प्रदूषकों और आंखों में प्रवेश करने वाले अन्य परेशानियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि, इन सबके बाद भी संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरतना और उचित स्वच्छता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कंजंक्टिवाइटिस बेहद संक्रामक है जैसे तौलिये, व्यक्तिगत सामान और यहां तक कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा पहने गए चश्मे के माध्यम से भी फैल सकता है। संक्रमण तब फैलता है जब कोई इन दूषित वस्तुओं को छूता है या किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आता है। कंजंक्टिवाइटिस को रोकने के लिए इन सेफ्टी टिप्स हाथों को साफ रखें और इन्हें बार-बार साबुन और पानी से धोते रहे। अपनी आंखों को धूल के कणों और प्रदूषकों से बचाने के लिए भीड़-भाड़ वाली जगहों पर धूप का चश्मा पहनें। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति की चीजों को सही तरीके से डिस्पोज करें। संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक सतहों को छूने से बचें।

संक्षिप्त खबरें

छात्रा के चयन पर खुशी जताई

उत्तरकाशी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी के लिए पुरोला के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 8वीं की छात्रा का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन होने पर शिक्षकों ने खुशी का इजहार कर छात्रा व मार्गदर्शक शिक्षक को बधाई देते हुते राज्य स्तर पर भी सफल होने की शुभकामनाएं दी।दो दिन पूर्व जनपद उत्तरकाशी में आयोजित जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक प्रदर्शनी में उच्च प्राथमिक विद्यालय कन्ताड़ी हुडोली की कक्षा 8वीं की छात्रा अंशिका के विज्ञान और प्रौधौगिकी में अनुसंधान के क्षेत्र में बनाये गए प्रोजेक्ट का चयन राज्य स्तर के लिए होने पर शिक्षक संगठन सहित अभिभावकों ने छात्रा की बधाई देते हुए शिक्षक यशवंत चौहान के प्रयासों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की।

पाटा व बग्याल गांव में वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया

उत्तरकाशी। जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव पाटा और बग्याल गांव में वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने ग्रामीणों ने वनों में आग से होने के वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ग्राम प्रधान नरेश चौहान व प्रथम नेगी की अध्यक्षता में आयोजित सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में बाड़ाहाट रेंज के वन क्षेत्राधिकारी मुकेश रतूड़ी ने कहा कि वनों में आग लगने या धुआं उठने पर तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग को दें। गोष्ठी में सुभाष प्रसाद, राधेश्याम बिजल्वाण, राजेंद्र सिंह राणा आदि थे।

कमल नदी में खनन को लेकर एसडीएम को दिया ज्ञापन

उत्तरकाशी। विकासखण्ड के सुनाली गांव के ग्रामीण महिलाओं ने कमल नदी पर हो रहे अवैध खनन को लेकर उप जिलाधिकारी देवानंद शर्मा से शिकायत करते हुए ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने खनन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। बुधवार को पुरोला के सुनाली गांव की महिलाओं ने प्रधान वीरेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी को कमल नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर ज्ञापन देते हुए खनन से खेतों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताईर। कमल नदी से रेत, पत्थर के अवैध खनन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि कमल नदी में गैर कानूनी ढंग से खनन माफिया बजरी व पत्थर रात को बेचने के लिए धड़ल्ले से नदी में खुदान कर रहे है, जिससे नदी किनारे ग्रामीणों की खेती के वर्षाकाल में बहने का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही अगस्त माह में आई बाढ़ के कारण क्षेत्र में काश्तकारों की कई हेक्टेयर कृषि भूमि बढ़ से नष्ट हुई है और अब खनन करने वाले ठेकेदारों के अवैध खनन से खेतों को ओर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ज्ञापन पर लायवीरी, बचनी देवी, कौशल्या भंडारी, राजो देवी, सावित्री, गजेंद्र, मनोज कुमार, अनीता देवी, बिरमा देवी, ओमप्रकाश, नीतीश आदि के हस्ताक्षर हैं।

कल से बूथों पर रात बिताएंगे भाजपा के लोग

उत्तरकाशी। गांव चलो अभियान, बूथ चलो अभियान के अंतर्गत भाजपा उत्तरकाशी के सभी 15 मण्डलों में कार्यशालाएं सम्पन्न होने के पश्चात 9 से 11 फरवरी तक प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता बूथों में जाकर 24 घण्टे का समय एक बूथ पर देगा। इसी क्रम में जिला अध्यक्ष सत्येन्द्र राणा पुरोला मण्डल के कण्डियाल गांव, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान सरनौल बूथ पर, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान भटवाड़ी मण्डल के सिल्ला, पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल कफनौल, दायित्वधारी राजकुमार नौगांव में, जिला महामंत्री पवन नौटियाल छिबाला बूथ पर, नागेन्द्र चौहान डिडसारी बूथ पर प्रवास करेंगे। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांवों में प्रवास करेंगे। गांव में 24 घण्टे के भीतर विभिन्न स्तर की बैठकें कर के बूथ व पन्ना प्रमुखों समितियों का सत्यापन करके केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।

यूसीसी को विधान सभा में पेश करने का तरीका अलोकतांत्रिकः कांग्रेस

विकासनगर। विधान सभा में समान नागरिक संहिता बिल ख(यूसीसी) को पेश करने के तरीके को कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया। बुधवार को ऐतिहासिक तिलक भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिल पेश करने से पहले सभी पक्षकारों और हितधारकों से विचार किया जाना चाहिए था। अल्पसंयक आयोग के पूर्व सदस्य एवं पीसीसी सदस्य संजय जैन ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में पेश किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड में अनेक विसंगतियां है। जिस तरीके से यह बिल विधानसभा में पेश किया गया, वह लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। लगभग 200 पेज के एक ड्राफ्ट बिल को अध्ययन करने के लिए भी विधानसभा के सदस्यों को समुचित समय प्रदान नहीं किया गया। बेहतर होता कि सरकार स्वच्छ मन और खुले दिल से इस बिल को पेश करती और इसके बाद ड्राफ्ट पर सभी पक्षकारों एवं हित धारकों से उनके विचार आमंत्रित किए जाते। इस दौरान अभिनव ठाकुर, कितेश जायसवाल, आशीष पुंडीर, शम्मी प्रकाश, बलजीत सिंह आदि मौजूद रहे।

बर्फबारी से चकराता के तीन ग्रामीण मार्ग बंद

विकासनगर। बीते दिनों हुई बर्फबारी से स्थानीय ग्रामीणों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। बुधवार को लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले तीन मार्ग बंद होने से ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकल पाए। ग्रामीणों की नगदी फसलें भी मंडी तक नहीं पहुंचीं। भारी बर्फबारी के चलते लोखंडी-लोहारी मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस मार्ग से करीब दस गांव जुड़े हुए हैं। आवागमन के लिए ग्रामीणों अन्य कोई साधन नहीं है। स्थानी बाशिंदे राजमोहन सिंह चौहान, गजेंद्र पंवार, सूपाराम जिनाटा ने बताया कि दो दिन से मार्ग बंद होने के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नगदी फसलें घर में ही पड़ी हुई हैं। सैंज-कुनैनत मोटर मार्ग भी दो जगहों पर बंद है। जबकि लेवरा मोटर मार्ग पर पूरी तरह से यातायात ठप है। दोनों मार्गों से जुड़े ग्रामीण दर्शन सिंह रावत, महेंद्र नेगी, सचिन जोशी ने बताया कि सर्दियों में बर्फबारी से हर साल मार्ग बंद हो जाते हैं, बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग की ओर से बर्फबारी से पहले मार्ग पर स्नो कटर की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। उधर लोनिवि चकराता के सहायक अभियंता आदित्य ठाकुर ने बताया कि सभी बंद मार्गों को खोलने के लिए जेसीबी भेज दी गई है। जल्द ही सभी मार्गों पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा।

ग्राफिक एरा में संतूर की धुन ने बांधा समां

देहरादून। प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित सतीश व्यास ने ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में प्रस्तुति दी। पंडित व्यास ने कार्यक्रम का आगाज़ संतूर पर शुद्ध राग बजाकर किया। तबला वादक अमित कवठेकर ने तबले पर अपने कौशल से बखूबी उनका साथ दिया। दोनों कलाकारों की जुगलबंदी ने दर्शकों को भाव विभोर कर खूब तालियां बटोरी। पंडित सतीश व्यास ने बताया कि प्राचीनकाल में शथातंत्र वीना कहा जाने वाला वाद्य यंत्र संतूर कश्मीर की सुरम्य वादियों से निकलकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रच बस गया है। सौ तारों वाला यह संतूर धनुष से निकले बाण की तरह ध्वनि उत्पन्न करता है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को शास्त्रीय संगीत में संतूर का महत्व भी बताया। कार्यक्रम में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी, शिक्षक शिक्षिकाएं और सैकड़ो छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

संपादकीय

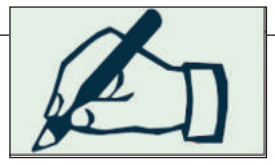

एक देश, एक संहिता क्यों?

समान नागरिक संहिता न तो सही है और न ही पूरी तरह गलत है। इसे लागू करने की भी जल्दी नहीं है, क्योंकि न तो संवैधानिक बाध्यता है और न ही तुरंत आवश्यकता है। गोवा भाजपा-शासित राज्य है, वहां नागरिक संहिता कानून के तौर पर लागू है। उत्तराखंड विधानसभा में नागरिक संहिता का बिल पेश किया जा चुका है। वह पारित भी हो जाएगा। गुजरात और असम ने भी ऐसी ही जुबान बोलनी शुरू कर दी है। ये सभी भाजपाई राज्य हैं। ऐसा नहीं है कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार संबंधी लैंगिक अन्याय को किसी ने संबोधित नहीं किया। केरल का उदाहरण सामने है, जहां 1975 में हिंदू विवाह कानून में संशोधन कर उत्तराधिकार अधिकारों में महिला को समानता दी गई। दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र ने भी उसका अनुसरण किया और कानून में सुधार किया। लैंगिक अपराध और दोष अब भी होंगे। ऐसा भी नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप की आड़ में ऐयाशी और टाइम पास संबंधों पर लगाम कसने के लिए समान नागरिक संहिता ही एकमात्र विकल्प है। उसके लिए अलग बिल पारित कर कानून बनाया जा सकता है। लिव इन के लिए बाकायदा पंजीकरण या माता-पिता की सहमति आदि के जो प्रावधान उत्तराखंड बिल में किए गए हैं, वे तत्संबंधी कानून में भी किए जा सकते हैं। वैसे भी लिव इन को नियंत्रित करने और विनियमित करने का काम नागरिक संहिता का नहीं है। यह नैतिक-पुलिस का ही उदाहरण है। बिल के मुताबिक, यदि लिव इन के पंजीकरण में विलंब होता है, तो आपको जेल में डाला जा सकता है और जुर्माना भी ठोंका जा सकता है। लिव इन संबंधी प्रावधान मध्यकालीन सामाजिक संहिता के हिस्से लगते हैं। बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि समान नागरिक संहिता से भारतीय जीवन पर पश्चिमी संस्कृति के अंधड़ के प्रभाव नहीं पड़ेंगे अथवा उनसे मुक्त हुआ जा सकेगा। हम तो संविधान और लोकतंत्र के लिए पश्चिम के ही मुखापेक्षी रहे हैं। सांस्कृतिक निशान कैसे मिट सकते हैं? सिर्फ बहुविवाह, हलाला, विवाह-तलाक के समान अधिकार और उत्तराधिकार के लिए, एक राज्य के स्तर पर, नागरिक संहिता की कोई तार्किकता नहीं है। बेशक संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को रखा गया है और सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी। दरअसल जब संविधान बनाया जा रहा था और आज की सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक परिस्थितियों में बड़े गहरे फासले हैं। संविधान में भी 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। सर्वोच्च अदालत ने भी नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी की है। उसके कथन का नए सिरे से अध्ययन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि देश में एक ही नागरिक संहिता की जरूरत है, तो केंद्र की मोदी सरकार नए जनादेश के बाद उस पर कार्रवाई शुरू करे। चुनावों से पहले राज्य-दर-राज्य में इसे लागू करना 'अन्याय की राजनीति' है, क्योंकि एक बहुत बड़ा भारतीय वर्ग इसके खिलाफ है। वे सडक़ों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, अराजकता और कानूनहीनता फैलेगी। क्या आम चुनाव से पहले ऐसा माहौल बनाना भी राजनीतिक रणनीति है? दरअसल समान नागरिक संहिता 1951 में 'जनसंघ' के गठन से ही प्रमुख बुनियादी एजेंडे का हिस्सा रही है।

दैनिक न्यूज़ वायरस
संपादक : मौ.सलीम सैफी, कार्यकारी संपादक : आशीष कुमार तिवारी न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मौ.सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से प्रकाशित एवं न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून से मुद्रित। **फ़ोन :** 0135-4066790, 2672002
RNI No. : UTTHIN/2012/44094 **Cert. Ser. No. :** 31406 **E-mail :** dainiknewsvirus@gmail.com
Website : www.newsvirusnetwork.com **YouTube :** TV News Virus
न्याय क्षेत्राधिकार : जनपद देहरादून (उत्तराखंड), भारत

देहरादून : दरोगा भर्ती मामले में सस्पेंड 20 दरोगाओं को राहत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 08 फरवरी : दरोगा भर्ती मामले में सस्पेंड चल रहे 20 दरोगाओं को पुलिस मुख्यालय ने बहाल कर दिया है। पिछले एक साल से सस्पेंड इन दरोगाओं के लिए ये बड़ी राहत है। मुख्यालय ने सभी सस्पेंड दरोगाओं की बहाली के आदेश दिए हैं। विजिलेंस की अंतिम रिपोर्ट और शासन के आदेश के बाद ही दरोगाओं पर आगे की कार्रवाई और उनके भविष्य का फैसला लिया जाएगा। एडीजी प्रशासन अमित सिन्हा ने सभी जिलों के कप्तानों को पत्र लिखकर सभी दरोगाओं को बहाल करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही सभी दरोगाओं को विजलेंस की जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा है।

मामले की जांच चलती रहेगी, अगर जांच में कोई दोषी मिला तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां आपको पूरा मामला भी बताते हैं। साल 2015-16 में कांग्रेस की तत्कालीन हरीश रावत सरकार के दौरान दरोगा के 339 पदों पर गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर ने सीधी भर्ती परीक्षा कराई थी। साल 2022 में जब यूकेएसएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में नकल और लेन-देन का पर्दाफाश हुआ तो साल 2015-16 में हुई दारोगा भर्ती में भी घपला होने की बात सामने आई थी।

इसके बाद दरोगा भर्ती परीक्षा की भी जांच हुई और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर जनवरी 2023 में 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया गया। इनमें जिला देहरादून से दरोगा ओमवीर सिंह, प्रवेश रावत, राज नारायण व्यास,जैनेंद्र राणा और निखिलेश बिष्ट, जिला ऊधमसिंहनगर से दरोगा दीपक कौशिक, अर्जुन सिंह, बीना पपोला, जगत सिंह शाही, हरीश महर, लोकेश और संतोषी, जिला नैनीताल से दरोगा नीरज चौहान, आरती पोखरियाल, प्रेमा कोरमा और भावना बिष्ट शामिल हैं। जबकि चमोली से गगन मैठाणी, जिला चंपावत से तेज कुमार और एसडीआरएफ में दरोगा मोहित सिंह रौथाण शामिल हैं।

फिलहाल इन सभी को राहत दे दी गई है। विजिलेंस की जांच जारी है। अंतिम रिपोर्ट के बाद शासन के आदेश पर ही दरोगाओं पर आगे की कार्रवाई और उनके भविष्य का फैसला लिया जाएगा।

नगर निगम हॉल में हुआ प्रशिक्षण कार्याशाला का आयोजन

देहरादून। जिलाधिकारी, देहरादून के मार्गदर्शन में महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी, देहरादून द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के सहयोग से विभिन्न हितधारको के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्याशाला का आयोजन नगर निगम हॉल देहरादून में किया गया। कार्यक्रम/प्रशिक्षण का शुभारम्भ मुख्य अतिथि मा0 जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून प्रदीप पंत द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को उक्त प्रशिक्षण का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।

प्रशिक्षण में संगीता गौड़, सहायक निदेशक ट्रेनिंग एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, कैलाश सत्यार्थी चिलड्रिन फॉउण्डेशन, नई दिल्ली एवं कैलाश सत्यार्थी फाउन्डेशन, नई दिल्ली के बबन प्रकाश द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों आदि के बारे में प्रतिभागियों / सभी हितधारकों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। सचिव/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून हर्ष यादव ने उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013, उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित / उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020, किशोर न्याय व्यवस्था में पुलिस की भूमिका के सम्बंध में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, बालकों के हित में उठाए जा रहे कदमों एवं अभियानों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण कार्यशाला में विभिन्न हितधारक पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड देहरादून, समस्त राकीय / स्वैच्छिक बाल गृहों के अधिक्षक व कार्मिक, चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई देहरादून के सभी कार्मिक द्वारा प्रतिभाग किया गया।

महिला कांग्रेस ने बढ़ते महिला अपराध पर साधा निशाना

देहरादून। महिला कांग्रेस ने 'नारी न्याय, हैं तैयार हम अभियान के तहत बढ़ते महिला अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस भवन में पत्रकारों से वार्ता में प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा शर्मा ने कहा कि पार्टी महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई लगातार लड़ती आ रही है। आगे भी इस संघर्ष को और तेज किया जाएगा।आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार महिला अपराध बढ़ रहे हैं। जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती रही है, उसके नेता इन अपराधों में आरोपी तक बनाए गए हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर पूरे राज्य में लगातार सामने आ रहे महिला उत्पीडऩ के मामलों को सरकार की नाकामी करार दिया। कहा कि उत्तराखंड में महिला कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मजबूती देने के लिए महिलाओं के सम्मान और न्याय की लड़ाई के लिए अभियान चला रही है। लगातार महिलाओं तक पहुंचकर उनकी विचारों को सुना जा रहा है। महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला ढौंडियाल थापा ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। महिलाएं भी इस बात को भलीभांति से जानने लगी हैं। इस मौके पर महिला कांग्रेस ने 'नारी न्याय, हैं तैयार हम का पोस्टर जारी कर महंगाई, समान काम के लिए समान वेतन, सामाजिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मामलों को उठाया। इस मौके पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा, महानगर अध्यक्ष उर्मिला ढौंडियाल थापा के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष नजमा खान, पुष्पा पंवार, चंद्रकला नेगी, अनुराधा तिवारी मौजूद रहीं।

पछुवादून के 87 छात्रों का राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति के लिए चयन

विकासनगर। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति-2023 में पछुवादून के कालसी ब्लॉक के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस परीक्षा में विकासखंड कालसी से सबसे अधिक 32, विकास नगर से 12, चकराता से 22 तथा सहसपुर से 21 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी कालसी भुवनेश्वर प्रसाद ने इस उत्कृष्ट प्रदर्शन का श्रेय विकासखंड के समस्त शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति में चयनित विद्यार्थियों को 12000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होते हैं। एक प्रश्न पत्र मानसिक योग्यता एवं दूसरा विषय आधारित विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान होता है। जिसके लिए विकासखंड स्तर से कुल 15 अभ्यास प्रश्न पत्रों की ओएमआर शीट पर प्रत्येक विद्यालय में तैयारी कराई गई।

देवभूमि व्यापार मण्डल अल्मोड़ा नगर इकाई का चुनाव 25 फरवरी को

अल्मोड़ा। देवभूमि व्यापार मण्डल, अल्मोड़ा की नगर इकाई के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी त्रिलोचन जोशी ने कहा कि देवभूमि नगर व्यापार मण्डल इकाई की चुनाव प्रक्रिया माँ नन्दादेवी मन्दिर परिसर के गीता भवन में चुनाव कार्यालय संचालित किया जायेगा। नगर इकाई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष एवं उपसचिव पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 12 फरवरी को नामांकन पत्र फार्म बिक्री, 13 फरवरी को नामांकन पत्र जमा, 14 फरवरी को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी, 15 फरवरी को नाम वापसी, 16 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा। 25 फरवरी को मतदान दिवस होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन फार्म बिक्री, नामांकन पत्र जमा करने, नामांकन पत्र जाँच, प्रत्याशी नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन का समय प्रातः 11 बजे से 04 बजे तक होगा।

मतदान का समय प्रातः 09 बजे से 02 बजे तक होगा। उसी दिवस अपराह्न 03 बजे से मतगणना आरम्भ होगी एवं परिणाम सायं 06:30 बजे घोषित होगा। चुनाव संचालन समिति में वरिष्ठ व्यापारी दिनेश गोयल, हरेन्द्र वर्मा, दीप लाल साह, अनूप गुप्ता आदि व्यापारी शामिल हैं। देवभूमि उद्योग व्यापार मण्डल के प्रदेश अध्यक्ष हुकुम सिंह कुँवर अल्मोड़ा नगर इकाई के चुनाव की निष्पक्ष निगरानी के लिए शीघ्र ही चुनाव पर्यवेक्षक एवं चुनाव प्रभारी के नामों की घोषणा करेंगे।

51 कुंडीय हवन के लिए भूमि पूजन किया

विकासनगर। गायत्री महायज्ञ एवं पवन प्रज्ञा पुराण कथा के लिए बुधवार को भूमि पूजन किया गया। कथा स्थल पर 51 कुण्डीय हवन किया जाएगा। गायत्री परिवार से शिवाकांत त्रिपाठी द्वारा विधि विधान पूर्वक हवन यज्ञ के साथ भूमि पूजन किया गया। पंडाल में लगभग हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ किया जाएगा। गायत्री परिवार प्रबंधक राधा कृष्ण सेमवाल ने बताया कि इस अनुष्ठान में हजारों श्रद्धालुओं की आने की संभावना है। इस दौरान हर्षवर्धन, सचिन चौधरी, दिनेश, विनोद कश्यप, धीरज चौधरी, सीएस जोशी, खुशबू, मधु सेमवाल, पार्वती पुंडीर, सुरेश डंगवाल आदि मौजूद रहे।

समानता, समरसता और सद्भाव कायम करेगा यूसीसी : स्वामी चिदानन्द

विविधता में एकता, एकता व अखंडता का जश्न है समान नागरिक संहिता

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ऋषिकेश, 8 जनवरी, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड विषय पर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने युवा मुख्यमंत्री, उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशवासियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिये बधाईयाँ दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र एक नई करवट ले रहा है ऐसे में दढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति की जरूरत है। यह ऐतिहासिक निर्णय लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमाल कर दिया; धमाल मचा दिया। यह समय शंका व शक का नहीं बल्कि हक का है।

स्वामी जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा करते हुये कहा कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन सीमित है और जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों पर जोर पड़ रहा है, समय से पहले समाप्त हो रहे हैं इसलिये एक सख्त कानून की जरूरत है। अब समय आ गया कि ''हम दो हमारे दो और सब के दो! जिसके दो उसी को दो'' नहीं तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। इस अवसर पर उन्होंने वाणी प्रदूषण, विचार प्रदूषण और वायु प्रदूषण न फैलाने का संदेश देते हुये कहा कि भारत शौर्य के साथ धैर्य की भी भूमि है। इस समय भारत की विशालता को भारत की दृष्टि से देखने की जरूरत है।

- एक राष्ट्र, एक विधान और एक निशान
- सब समान, सबका सम्मान यही है भारत का संविधान
- समान नागरिक संहित सियासत का नहीं विरासत का विषय
- लिव - इन रिलेशनशिप ''यह अनुबंध नहीं संबंध है'' - स्वामी चिदानन्द

ज्ञात हो कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अन्तर्गत है। जिसमें कहा गया है कि ''राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।'' यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लिए पूरे देश में एक ही नियम। दूसरे शब्दों में कहें तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून का होना।

यूसीसी लागू करने से राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा। यह धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता के लिये खतरा नहीं है बल्कि इससे एकता, एकरूपता और सद्भाव के वातावरण का निर्माण होगा। समान नागरिक संहिता से पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान होगी और धार्मिक विभाजन को कम करने में मदद मिलेगी, परस्पर विश्वास प्रगाढ़ होगा, धार्मिक रूढ़िवादिता के बजाय लोकहित के कार्य होगे।

यूसीसी का प्रवर्तन कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करेगा, कानूनों को सरलीकृत करेगा और धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का पालन करते हुए लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। साथ ही समानता, बंधुता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को भी संपुष्ट करेगा। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और उत्पीड़न को दूर करके लैंगिक न्याय एवं समानता सुनिश्चित करेगा।

वोटर जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून , 8 फरवरी , मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम ने आगामी लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए वोटर जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए स्वीप गतिविधियों के साथ ही प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का सहयोग लिया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को वोटर जागरूकता कार्यक्रमों से जोड़ा जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बी वी आर सी पुरुषोत्तम सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में नोडल अधिकारियों के साथ निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। डॉ पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर सभी तैयारियां पूरी की जाएं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्लान और आयोग के मानकों के अनुरूप स्टेट डिप्लॉयमेंट प्लान बना लिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन से जुड़े कार्मिकों की ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि कार्मिक पूरी गंभीरता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ पुरुषोत्तम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सी विजिल जैसी अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। लोगों तक इसकी जानकारी अधिकाधिक पहुंचाई जाए। वोट प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बूथ वार रणनीति बनाई जाये। बूथ स्तरीय जागरूकता समूहों को सक्रिय किया जाए।

डीएम ने ग्रामीण निर्माण विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा

न्यूज वायरस नेटवर्क

चमोली। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बुधवार को ग्रामीण निर्माण विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की प्रगति समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कार्य पूर्ण हो चुके है उनको संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए। जिन कार्यो में टेंडर कर लिए गए है, उनमें शीघ्र कार्य प्रारंभ करें। विभागीय अधिकारी संचालित निर्माण कार्यो की स्वयं मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्यो में तेजी लाते हुए गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण हेतु जहां भूमि उपलब्ध नहीं है वहां जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों से सहयोग लेकर भूमि चिन्हित की जाए। आपदा मद में धनराशि उपलब्ध हो चुकी है। आपदा मद से जो भी कार्य प्रस्तावित है उनके लिए भी शीघ्र टेंडर करते हुए कार्य शुरू किया जाए।

ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अला दिया ने बताया कि जिला योजना, राज्य सेक्टर तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन विभाग के 02, शिक्षा विभाग के 94, स्वास्थ्य विभाग के 46, राजस्व के 11, बाल विकास के 25, समाज कल्याण के 04 सहित कुल 199 कार्य थे। जिनमें से 57 कार्य पूर्ण और अवशेष योजनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ अभिषेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आनंद सिंह, अधिशासी अभियंता अला दिया, सहायक अभियंता एलपी भट्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलदीप गैरोला, एसीएमओ डॉ वीपी सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

संक्षप्ति खबरें

सब रजिस्ट्रार के खिलाफ अधिवक्ताओ ने करी नारेबाजी

नैनीताल। जिला न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ताओ ने सब रजिस्ट्रार द्वारा की जा रही अनिमितताओं पर नारेबाजी करने के साथ ही अधिवक्ताओ ने अपर जिलाधिकारी फिंचा राम को सब रजिस्ट्रार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा अधिवक्ताओ ने बुधवार को रजिस्ट्री कार्यालय में कार्यरत सब रजिस्ट्रार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुवे सब रजिस्ट्रार पर अनिमितताओं का आरोप लगाते लगाया कहा कि सब रजिस्ट्रार भूमाफियों के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों व सगे संबंधियों को लाभ पहुचा रही है सब रजिस्ट्रार अपने रिश्तेदारों से ही रजिस्ट्री करवा कर उन्हें सीधे अनुचित लाभ पहुचा रही है कहा आम लोगो को कागजात होने पर भी उनकी रजिस्ट्री नही की जा वही अपने रिश्तेदारों द्वारा रजिस्ट्री करवाने पर कोई परेशानी न होने की बात कही जा रही है अधिवक्ताओ ने अपर जिलाधिकारी फिंचा राम को सब रजिस्ट्रार के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। वही अपर जिलाधिकारी फिंचा राम ने अधिवक्ताओ की शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुवे सब रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण मांगते दे अपना पक्ष बताने को कहा है। इस दौरान जिला बार के अध्यक्ष मनीष मोहन जोशी दया किशन पोखरिया संजय सुयाल दीपक रुबाली राकेश सुयाल कमल मनोज लोहनी विपिन पंत राजेन्द्र चिलवाल डी एस सूर्या पूरन बिष्ट प्रमोद तिवारी शिवांशु जोशी दीपक दानू अनिल कुमार भरत सूर्या हरीश आर्या आदि मौजूद रहे।

शिक्षा महकमे के कार्मिकों ने रखी समस्याएं

नैनीताल। एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन की मंडल शाखा ने विभिन्न समस्याओं को लेकर अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं लीलाधर व्यास से वार्ता की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने लंबित मांगों का तत्काल निस्तारण करने की मांग उठाई। एडी ने जल्द ही कार्मिकों की समस्याओं का निस्तारण करने का भरोसा दिया। अपर निदेशक व्यास ने कहा कि लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए शिथिलीकरण को लेकर सूची जारी कर दी गई है। कनिष्ठ एवं वरिष्ठ सहायकों की पारस्परिक स्थानांतरण सूची दो दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा स्थायीकरण, मृतक आश्रित प्रकरणों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। संगठन के मंडलीय अध्यक्ष पुष्कर सिंह भैसोड़ा एवं सचिव हरप्रीत सिंह ने अपर निदेशक का स्वागत करते हुए समस्याओं के तत्काल निस्तारण की मांग की। यहां पर जिलाध्यक्ष यूएस नगर वीरेंद्र पांडे, सचिव अल्मोड़ा मुकेश चंद्र जोशी, सचिव नैनीताल चंचल ल्वेशाली, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संतोष कुमार, अनिल कुमार गुप्ता, जय प्रकाश, जीवन सिंह बिष्ट, जगमेहत रौतेला, कमल फुलारा, राकेश पाठक, गोपाल विष्ट आदि रहे।

'नियमित रोजगार की जगह बिना कारण जा रही नौकरी'

रुद्रपुर। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने ऊधमसिंह नगर के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारियों के साथ गेट मीटिंग की। बुधवार को उपनल संविदा कर्मचारियों ने विकास भवन के गेट पर उपनल संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बैठक की। उपनल कर्मचारियों ने कहा कि सरकार को उपनल संविदा कर्मचारी की समस्याओं के निस्तारण के लिए शासन को पत्र भेजे गए हैं। इनका निस्तारण नहीं किया गया है। राज्य गठन के बाद उपनल कर्मचारी निगमों, विभागों में पिछले 15 से 18 वर्ष से अल्पवेतन में काम कर रहे हैं, लेकिल सरकार उपनल संविदा कर्मचारियों को नियमित रोजगार देने के बदले उनको बिना किसी कारण बताए नौकरी से हटा रही है। कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन दिया जा रहा है और न ही महंगाई के अनुरूप वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है। उपनल कर्मचारियों ने कहा कि यदि सरकार 12 फरवरी से पहले उपनल कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो उपनल कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर आन्दोलन को मजबूर होंगे।